आदिमजनजाति बिरहोर – कम होता शिक्षा का स्तर

जिम्मेदार सरकार और गैरसरकारी संस्थाएं

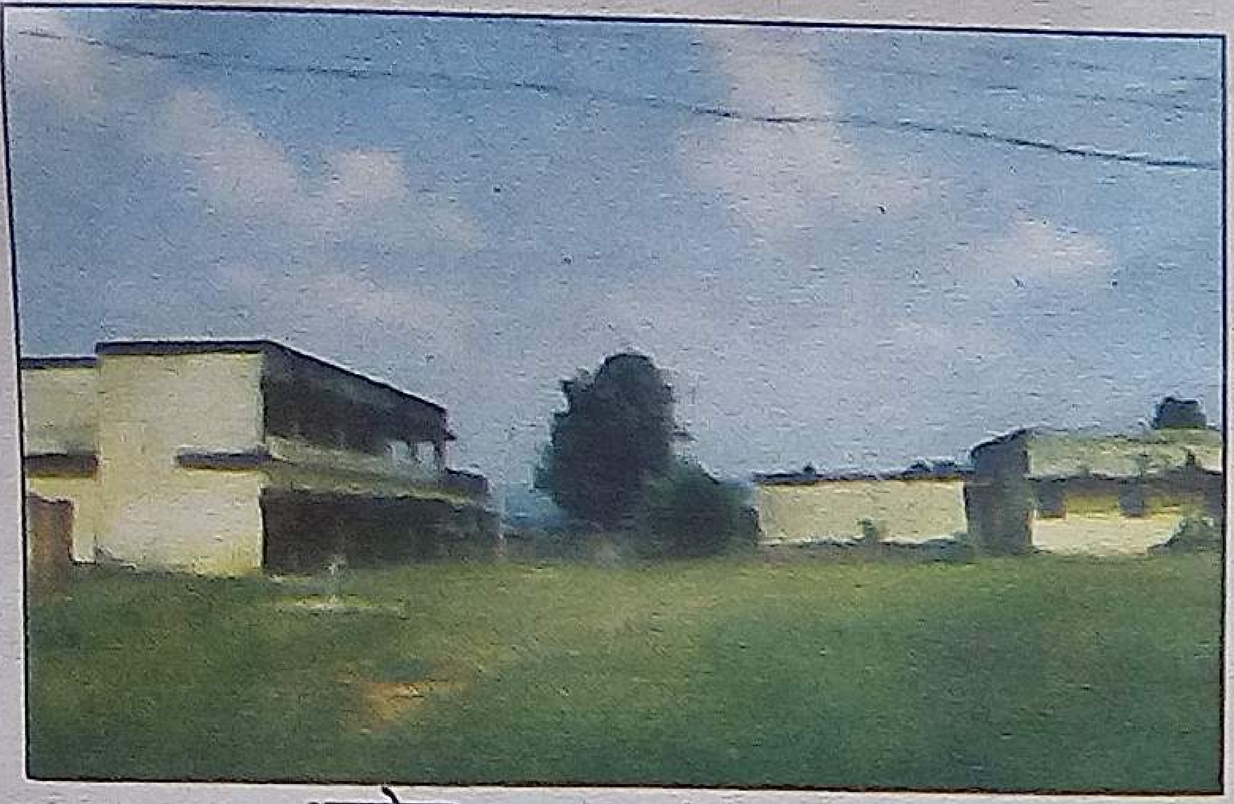

आलोका

सीएसडीएस/ यूएनडीपी फेलोसिप के तहत झारखंड के अनुसूचित राज्य है, 24 जिला वाला यह राज्य के हर जिले में अनुसूचित जनजाति के शिक्षा के लिए मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय बालिका विद्यालय की स्थापना की गयी है. जिसमें लगभग 24 जिले में यह विद्यालय संचालित है वहां आदिवासी बच्चों के अलावा बिरहोर समूदाय के बच्चों भी पड़ते है. जिसमें सबसे सुदूर गांव के बच्चों के लिए यह व्यवस्था है. इस शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संस्था ने कभी प्राथिमिकता की सूची में नहीं रखा. बदलते शिक्षा व्यवस्था में झारखंड में शिक्षा और शिक्षित होने के लिए बिरहोर समूदाय को प्रेरित कर दिया है. जंगल का वह भाग जहां कभी सूरज के रौशनी के अलावे और कुछ नहीं पहुंचता था. आज वहां बच्चे अपने को शिक्षित करने के लिए गांव से बाहर अनुसूचित जनजाति विद्यालय में जा रहे है. जंगल का घनापन खत्म हो रहा है. जंगल के अन्दर और जंगल पर निर्भर लोगों के पास संकट आया है. उनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन आ चुका है इन समूदाय के बीच अब संसाधन का अभाव दिखने लगे है. इनके जीवन में पूंजी का महत्व बढ़ा है आर्थिक सबलता बनने के लिए लिखना पढ़ना और डिग्री लेने के प्रति रूचि जग गयी है 60 साल पहले की स्थिति अब बिरहोर के गांव में नहीं रही. उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन आने लगा है. उनके हिस्से का वन और वनप्राणी अब जंगल के समाप्त होने से उनके उपर संकट आ गया. संकट से उबरने के लिए उन्होंने शिक्षा को भी एक रास्ता को चुना. 24 जिले वाला झारखंड में बिरहोर शिक्षा का स्तर में अक्षर ज्ञान के अलावा नन मैटिक और इंटर तक की शिक्षा लिए हुए लोगो की संख्या 2 प्रतिशत तक आ गयी है. छोटी आबादी अपने को बचाने के लिए मुख्यधारा के साथ जुड रहे है वे बहारी समाज के साथ अपने के बीच मेल मिलाप बढ़ा रहे है. नौकरी और की ओर बढ़ रहे है. जिससे उनके रहन- सहन में परिवर्तन होता जा रहा है अब वह शिक्षित हो कर परिवार और समाज के बीच रहना ज्यादा पंसद करने लगे है.

अनुसूचित जन जाति के विद्यालय

सरकार ने अनके लिए अवासीय विद्यालय की व्यवस्था कर दिये है पर उनके शिक्षा का स्तर दर अब भी कम है दो स्कूल उदाहरण के रूप में हम देखते है एक तो रांची की राजधानी से 150 किमी दूर गुमला के विशूनपूर के आदिमजनजाति आवासिय विद्यालय दुसरा रांची के राजधानी के मुख्यालय से 23 किमी के बुण्डू ब्लॉक के स्थित आवासिय विद्यालय की स्थिति जिसमें जिसमें गुमला के विशूनपूर के विद्यालय में बंद पड़े है उस विद्यालय के बिहार के संस्था को संचालित करने के लिए दे दिया गया है जहां एक भी स्थानिय यानि की जहनगुटूआ के एक भी बच्चे नहीं जाते है. वहां पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के है. लम्बे समय से विद्यालय बंद रहता है. बाहर से देखने से लगा इसकी स्थिति खंडहर जैसे है वहां कभी विद्यालय खुलता ही नहीं है. आसपास के लोगो से जानकारी लेने पर बच्चों ने बताया की यह विद्यालय में स्थानिय लोग पड़ने नही जाते है गांव के क्षत्रपति ने बताया की गांव में लोग शिक्षत है पर सरकार इनको शिक्षा के काम में नहीं लगाती है. और न गांव में शिक्षा समिति का गठन किया गया है. बिजय बिरहोर ने बताया की गांव के बच्चे बाहर के स्कूल मे जाते है. इस लिए की यहां शिक्षा के लिए शिक्षक की कमी है और सही तरीके से पढ़ाई नही हो पाती है. हमारे गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र है यहां के स्थानिय महिला द्वारा संचालित है जिसमें 40 बच्चे जाते है. लेकिन आवासिय विद्यालय में हमारे गांव के एक भी बच्चा नही जाता है.

वही बुंडू के अमनबुरू में 6 स्कल बिल्डिंग है. जिसमें 5 में स्कूल और एक में आवासीया विद्यालय है जिसमें 88 बच्चे है. 7 शिक्षक है जिसमें पहला क्लास से लेकर 6 क्लास तक की पढ़ाई होती है. विद्यालय बनने के बाद कभी मरामत नहीं किया गया. आधे से अधिक क्लास रूम टूट चुके है. पीने के पानी का संकट हर वक्त बना रहता है. सरकार रहने के लिए उचित व्यवस्था करने में असमर्थ है स्कूल में के लिए तमाम संसाघन है पर वह इन बच्चों को नहीं मिलता है. रमेश शंकर मुंडा ने बताया की हमारे यहां 6वीं तक क्लास होती है इससे 12 तक क्लास करने की मांग 2007 से लगातार किया गया. जब रांची के डीसी के के सोन रहे थे तो उन्होने कहा था इसे उच्च विद्यालय बना कर रहेंगे लेकिन सोन बदल गये. नये डीसी आये जिसने कभी हमारी सुनी तक नहीं. न हमारे पास कभी आये. सुमन मुण्डा जो स्कूल के प्रधानमंत्री है ने बताया की हम दुसरे स्कूल के बारे नहीं जानते है पर हमें तमाम विषय पर शिक्षा मिलनी चाहिए जिसके लिए शिक्षक नहीं है. शिक्षक के आभाव में हम अच्छी शिक्षा से वंचित रह रहे है. वही सुनील बिरहोर ने बताया की हमारा घर अमनबुरू में है हम बीच बीच में घर जाते है रहते है चार क्लास में पढ़ते है. यहा तो सब टूटा हुआ है मास्टर हमें पढ़ाते है पर क्लास रूप का अभाव है. महेश्वर लोहरा ने बताया की हम 6वी क्लास में पढ़ रहे है इसके बाद हम कहा पढ़ने जाएगे यह हमारे लिए चितां का विषय है.

बच्चों ने रखा प्रस्ताव

बच्चों ने कहा हमारे स्कूल में कम्प्यूटर की शिक्षा शुरू किया जाए. फुटबॉल की व्यवस्था की जाए. खेलने के लिए सरकार की और से जूते दिये जाए. खेल और कला संस्कृति की शिक्षक की नियुक्त हो. स्कूल को 12 तक पढ़ाई शुरू किया जाना चाहिए यदि सरकार हमारे यह प्रस्ताव को मान लेगी तो हमारा विद्यालय अन्य विद्यालय से अच्छा हो जाएगा.

बिरहोर शिक्षित बेरोजगार

अमनबुरू में हर घर में शिक्षित व्यक्ति है 8 कलास तक के शिक्षा सब के पास है वे अब अपने को मानते है शिक्षित बेरोजगार दुबराज बिरहोर नन मैटिक है उन्हे पता है सरकार उनके लिए विशेष नौकरी की व्यवस्था किये है पर वह नहीं जानते है की वह कहां जाकर नौकरी की मांग करे. उसकी पत्नी हजारीबाग में आंगनबाडी सेविका है. वही सुरेश बिरहोर सिल्ली में पलायन कर गया है, वहां बिरहोर समूदाय के बीच काम करते है. बीच बीच में अपने गांव आते है. अमनबुरू और ढीपा टोली से 12 लड़के स्कूल जाते है 04 लडकीयां कस्तूरबा गांधी स्कूल में रह कर पढ़ाई करती है. गांव में शिक्षित बहु लाने की प्रथा हर हर घर में बहु नन मैटिक या 8वी तक की पड़ाई कर चुकी है.

अमन बूरू आवासीय विद्यालय के शिक्षक प्रमेश्वर लोहरा ने बताया की बुण्डू के गांव में बिरहोर अब धीरे- धीरे शिक्षत हो रहे है रोजगार से जुड रहे है पलायन कर दूसरे स्थानों में रोजगार खोज रहे है बच्चे स्कूल में रहते है. स्कूल में शिक्षक की कमी है. सरकार व्यवस्था करेगी तभी संभव हो पाएगा. शिक्षा के प्रति बच्चों को काफी इच्छा है. 6वी तक की पढ़ाई के बाद बच्चे भटक जाते है. इसका विकल्प नहीं खोज पा रहे है अन्य स्कूल काफी दूर है जहां बच्चों के रहने की व्यवस्था नहीं है इस लिए उच्च शिक्षका के प्रति थोड़ी उदासीनता है. गांव के ग्राम प्रधान ने बताया कि हम हर रविवार को गांव सभा की बैठक करते है उसमें शिक्षा के सवाल को उठाते है सरकार हमारी नहीं सुनती है हम चाहते है तकनीकी शिक्षा के साथ अन्य शिक्षा के साथ बच्चों को जोड़ा जाए जो हमारे गांव में नहीं है. समय परिवर्त हो चुका है शिक्षा में भी परिवर्तन आ रहा है. लेकिन हमारे गांव में पुराने नियम कायदे से शिक्षा चल रही है इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है.

आदिमजनजाति के स्कूल बेहाल : झारखंड में सरकार ने आदिमजनजाति के लिए उच्च विद्यालय 248 और मध्य विद्यालय 88 विद्यालय की स्थापन कर संचालित तो कर रही है पर इसकी बदहाली और गरीबी से उबरने के लिए कभी प्रयास नहीं किया है. शिक्षा अधिकार कानून के तहत इन स्कूलों में वो तमाम व्यवस्था बच्चे को नहीं मिल पा रही जिसका वे हकदार है. तकनीकी युग में हर स्कूल कम्प्यूर से जहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वही आदिमजनजाति बिरहोर के बच्चे आज भी पुरानी पद्धति से शिक्षा लेने के लिए मजबूर है. सरकार ने लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ने दोनो के बीच दूर बना दिया है. कस्तूरबा गांधी स्कूल में लड़कियों के लिए शिक्षा का जो व्यवस्था है वह व्यवस्था आदिमजनजाति विद्यालय में लड़कों को नहीं मिल पा रहा है. ऐसे स्थिति मे समाज में बराबरी की शिक्षा का सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगता है.

अनुसूचित जनजाति उपयोजना का बजट 2014-15 राशि

कुल आवंटित बजट / अनुसूचित जनजाति में आबंटित बजट	2012-13 ए ड	1213-14 बी ई	1213-14 आर ई	1215-15 आरई
अनुसूचित जनजाति में	12438.010	19151.90	17949.370	26754.970
आबंटित बजट प्रतिशत	5217.800	8866.505	6816.258	7965.010
कुल कितना बजट	41.95	46.30	37.97	29.77
आंबटित होना चाहिए था जनसंख्या के अनुसार	3233.8826	4979.494	4666.8362	6956.2922

बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर चल रहे हजार संस्था

इंटरनेट में शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्थाओं के लम्बीकतार मौजूद है. कई फंडिग एजेंसी भी शिक्षा के लिए झारखंड में काम करने के लिए फंड दिए गये है. ऐसे हजार संस्था है जिनके पास बच्चों के शिक्षा के लिए काम तो कर रही पर वह आदिमजनजाति के अन्तर्गत अति पीछड़ा वर्ग पीटीजी के लिए किसी संस्था ने ने अपना काम करना शुरू नहीं किया है. शिक्षा के अधिकार के लिए नये नारे के बीच इन समूदाय के बीच कॉलेज की शिक्षा से बेखबर है रांची में कल्याण विभाग छोड़ आदिमजनजाति के बच्चों के लिए कोई सुध लेने वाला नहीं है. राज्य सरकार और गैरसरकारी संस्थान ने आदिमजनजाति के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण तरीके से काम नहीं किया जिससे आदिमजनजाति के बिरहोर समूदाय को शिक्षा के माध्यम से उच्च स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा है.

अनुसूचित जनजाति सरकार की उपयोजना में शिक्षा पर बजट कम

झारखंड में अनुसचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना की स्थिति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 26 प्रतिशत है वही पीटीजी की आबादी सबसे कम होती जा रही है इसी जनगण्ना के अनुसार इस वर्ष 2014 15 के बजट में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए योजना बजट में से 26 प्रतिशत राशि आदिवासी समुदाय के लिए आंबटित किया जाना चाहिए.

स्रोत राज्य प्लान 2014 – 15 झारखंड सरकार

वितीय वर्ष 2014-15 का झारखंड सरकार द्वारा अनुमानित कुल प्लान बजट रुपये 26754.97 करोड़ है. जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए रुपये 7965.010 करोड आंबटित किये गए है जो की जनसंख्या अनुपात के अनुसार से कहीं अधिक है. विश्लेषण के अनुसार यह बात सामने आता है की वैसे तो आबंटन कहीं अधिक किया जाता है, परन्तु इस आवंटन का सीधा लाभ जन समुदाय को नहीं मिलता.

शिक्षा विभाग में आंबटित बजट

झारखंड सरकार ने प्राथमिक शिक्षा विभाग में टीएसपी तथा एस सी एस पी के अन्तर्गत सबसे बड़ा आबंटन बच्चों के लिए पोषक आहार योजना में किया है. जिसकी राशि टीएसपी में 82.56 करोड़ है तथा एस सी एस पी में रुपये 32.64 है. यह योजना एक जरूरी एवं महत्वकांक्षी योजना है. जिसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका सीधा लाभ आदिवासी और आदिमजनजाति के बच्चे तक पहुंचे.

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी सामान्य श्रेणी की लड़कियों के लिए मुफ्त साईकिल वितरण करने हेतू उपयोजना के 1.6 करोड़ आबंटित किये गए है. उच्च शिक्षा विभाग मं भी सरकार ने उपयोजना के अंतर्गत रांची विश्वधिलय को 8 करोड़ का अनुदान, दुमका विश्वधिालय को 8 करोड़ का अनुदान, कोल्हान को 7 करोड़ का अनुदान दिये गये जिसका सीधा लाभ आदिमजनजाति के समुदाय को नहीं हो पा रहा है.

कल्याण विभाग में झारखंड सरकार ने आदिवासी क्षत्रों में शिक्षा हेतु 130 करोड़ का अनुदान और धारा 275 ए एडिसनल टी एस पी के अंतर्गत टीएसपी से रुपये 100 करोड़ का अनुदान दिया है जो सराहनीय है. टीएसपी से ही रुपये 30 करोड़ की पोस्ट एँटैस छात्रवृति तथा रुपये 30 करोड़ की प्राथमिकशाला छात्रवृति रुपये 20 करोड़ की माध्यमिकशाला छात्रवृति रुपये 15 करोड़ की उच्चशाला छात्रवृति का भी प्रावधान किया है. यह सारी योजनाएं छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ पहुंचती है और नियमों के अनुसार है तथा उनके शिक्षा विकास भी सहायक है. इसलिए इस प्रकार की योजनाओं में राशि बढ़ाई जानी चाहिए. सरकार चाहती तो यह पैसा का उपयोग आदिमजनजाति के बिरहोर बच्चों के उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए उपयोग कर सकती थी. इसके बाद भी आदिमजनजाति बिरहोर के बच्चे के शिक्षा का स्तर उठ नहीं पा रहा है कहीं न कहीं सरकार और गैरसरकारी संस्था से चुक हो रही है.